प्रदेश के खजाने में आए 4.26 लाख करोड़

केंद्रीय करों के अंश के रूप में देश में सबसे ज्यादा 2.68 लाख करोड़ मिले...अन्य मदों में 1.58 लाख करोड़

अभिषेक गुप्ता

लखनऊ। केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप में कृपा बरसी है। मोदी सरकार के खजाने से योगी सरकार की तिजोरी में लगभग 4.26 लाख करोड़ रुपये आएंगे। अलग-अलग मदों के रूप में राज्य सरकार को मिलने वाली ये धनराशि पिछले बजट की तुलना में 25 हजार करोड़ रुपये ज्यादा है। इसमें केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, कैपिटल असिस्टेंस, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में हिस्सेदारी, सेंट्रल सेक्टर और वित्त आयोग के तहत मिलने वाली धनराशि शामिल है।

केंद्रीय करों में यूपी की हिस्सेदारी देश के सभी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 2.68 लाख करोड़ रुपये योगी सरकार को इसी मद में मिलेंगे। इससे प्रदेश सरकार को विकास कार्यों को तेज करने और जनकल्याण योजनाओं को विस्तार देने में बड़ा सहारा मिलेगा। इस धनराशि से उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास और ग्रामीण योजनाओं को नई गति मिलेगी। खास तौर पर एक्सप्रेसवे, मेट्रो परियोजनाएं, औद्योगिक कॉरिडोर और स्मार्ट सिटी जैसी योजनाओं के लिए यह फंड अहम साबित होगा। कुल केंद्रीय राज्यांश में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 17.61% रही है। इसके अलावा स्पेशल कैपिटल असिस्टेंस फार स्टेट स्कीम के तहत मिलने वाले फंड में 20 हजार करोड़ आएंगे। पिछले वर्ष 18 हजार करोड़ रुपये मिले थे।

इस स्कीम के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि ब्याजमुक्त होती है, जिसकी वापसी का समय 50 वर्ष है। बजट में महिलाओं, युवाओं और छोटे उद्यमियों को खास ध्यान रखा गया है। ये बजट राज्य को 10 खरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा।

>> विशेष पेज : प्रदेश पर असर : पेज 2,8,9

सड़कों, पुलों के लिए 50 साल तक ब्याजमुक्त 10 हजार करोड़

प्रदेश में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए केंद्र से 10 हजार करोड़ रुपये मिलेंगे। राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता (एसएएससीआई) स्कीम के तहत 50 साल के लिए यह राशि ब्याज मुक्त ऋण के तौर पर मिलेगी।

12 हजार आईटी-बीपीओ को टैक्स राहत : प्रदेश के आईटी, बीपीओ और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग (केपीओ) सेक्टर को बड़ी राहत मिली है। जीएसटी कानून की धारा 13(8) से जुड़े प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव है। इससे विदेशी कंपनियों को दी जाने वाली सेवाओं पर लग रहा 18 प्रतिशत जीएसटी समाप्त हो जाएगा।

पशुपालन से किसानों की मजबूती : प्रदेश के पशुधन की सेहत सुधार में इजाफा होगा। पशुओं की जांच हो सकेगी। कॉलेज स्थापना से समय पर गर्भाधान की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों को मजबूती मिलेगी।

केंद्रीय करों में यूपी का हिस्सा

अलग-अलग मदों में बढ़ी यूपी की हिस्सेदारी

मद	राशि (वर्ष 25-26)	राशि (वर्ष 26-27)
केंद्रीय करों में राज्यांश	2.55 लाख करोड़	2.68 लाख करोड़
केंद्र प्रायोजित स्कीम	90 हजार करोड़	1.10 लाख करोड़
कैपिटल असिस्टेंस	18 हजार करोड़	20 हजार करोड़
सेंट्रल सेक्टर	15 हजार करोड़	18 हजार करोड़
अन्य मद (लोन आदि)	10 हजार करोड़	10 हजार करोड़
कुल	4.01 लाख करोड़	4.26 लाख करोड़

केंद्रीय बजट में हर तबके का रखा ध्यान

केंद्रीय बजट में नए व विकसित भारत की संकल्पना की दृष्टि दिखाई देती है। 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक के पूंजी व्यय, सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर और 7 रेल कारिडोर के लिए बजट में प्रावधान है। आयुष सेक्टर को विकसित करने और हेल्थ सेक्टर की मजबूती के प्रयास किए गए हैं। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, स्टेम (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग व मैथ्स) संस्थानों की स्थापना और बेहतरीन इन्फ्रास्ट्रक्चर से युक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के काम बजट में शामिल करना सराहनीय है। यह अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाने में मददगार साबित होगा। युवाओं, महिलाओं, किसानों, उद्यमियों व आम नागरिकों को नए अवसर मिलेंगे। यह हर तबके (युवा, महिला, किसान, उद्यमी) को ध्यान में रखकर बनाया गया है। – योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री